C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY/169/2015-2017

प्रखर...मुखर...स्वर

विदर्भ की बात SUNDAY

● वर्ष 17 ● अंक 223 नागपुर, रविवार, 9 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

एलओसी के पास पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, सेना के एक जवान और उसकी पत्नी की मौत

जम्मू

पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को संघर्षविराम का उल्लंघन कर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटी अग्रिम चौकियों एवं बस्तियों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के एक जवान और उसकी पत्नी की मौत हो गयी तथा उनकी तीन बेटियां घायल हो गयीं। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्षविराम उल्लंघन किया और नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटी भारतीय सैन्य चौकियों पर शनिवार को सुबह साढ़े छह बजे से छोटे एवं स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी एवं मोर्टार दागने शुरू कर दिये। उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों ने इसका माकूल जवाब दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना की ओर से हुए मोर्टार हमलों में छुट्टी पर चल रहे प्रादेशिक सेना के सिपाही मोहम्मद शौकत और उसकी पत्नी साफिया बी की मौत हो गयी। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दागा गया एक मोर्टार करमारा स्थित सिपाही के घर के पास फटा। मोर्टार हमले में दंपति की तीन बेटियां जायदा कौसर (छह), रबीना कौसर (12) एवं नाजिया बी और अन्य लोग घायल हो गये।

पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी और गोलाबारी की। उन्होंने कहा, खादी, करमारा और गुपलूर जैसे इलाकों में भारी गोलाबारी जारी है।

अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना आठ विभिन्न चौकियों से एलओसी के पास स्थित गांवों और अग्रिम चौकियों पर भारी गोलाबारी कर रही है। उसने पांच से छह बस्तियों पर गोलीबारी की है।

राजस्थान के बीकानेर में एक सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, चार घायल

बीकानेर

राजस्थान के चुरु जिले में एक सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई और अन्य चार घायल हो गए। यह घटना सादुलपुर-चुरू राजमार्ग पर तब हुई, जब बस तकनीकी खराबी आ जाने के कारण सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी वक्त सामने से तेज गति से आ रही एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी जिसके चलते बस में बैठी तीन महिलाओं की तत्काल मौत हो गई। मृतक महिलाओं के नाम तना देवी, भंवरी देवी और गीता देवी है। पुलिस ने बताया कि, बस के किनारे खड़ी होने के बावजूद ये महिलाएं बस के केबिन में ही थीं जबकि अन्य यात्री बस के बाहर आ गए थे। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज चुरु में एक स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है।

जी-20 सम्मेलन: ब्रिटेन की पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा-आर्थिक अपराधियों को हमें सौंप दें

हैम्बर्ग

जर्मनी के हैम्बर्ग में चल रहे जी-20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन की पीएम टेरेसा से मुलाकात की और उनके समक्ष भारत के आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी की इस पहल से भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। विजय माल्या और ललित मोदी के खिलाफ भारत में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं।

गौरतलब है कि शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारत के 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। माल्या ने अपनी

संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस को उबारने के लिए इन बैंकों से कर्ज लिया था।

इसके बाद बैंक कंसोर्टियम उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने की अपील के साथ मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो माल्या इंग्लैंड भाग गए। इस बीच भारत सरकार की तरफ उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश शुरू की गई और फिलहाल उनके प्रत्यर्पण का केस ब्रिटिश अदालत में विचाराधीन है।

आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी हैं फरार

आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी फरार हैं और ब्रिटेन में रहते हैं। ललित पर आइपीएल का कमिश्नर रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है।

ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भारतीय एजेंसियां दोनों माल्या और मोदी का प्रत्यर्पण करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पायी है।

पीएम मोदी ने इससे पहले इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी और दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। इसके अलावा मेक्सिको, अर्जेंटीना, वियतनाम के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है।

महाराष्ट्र के सतारा में कल पीएपी के पुनर्वास पर सम्मेलन

मुंबई

महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित 65 लाख से अधिक लोगों के प्रतिनिधियों ने कल 10 जुलाई को राज्य के सतारा जिले के पुनर्वासित गांव में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में परियोजना प्रभावित लोग (पीएपी) के पुनर्वास का मुद्दा बहुत पुराना है और इससे पिछले 50 से अधिक वर्षों में 65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जनजागर प्रतिष्ठान के माधव भंडारी और इनके प्रतिनिधि ने कहा, जब मैंने सतारा जिले के एक पुनर्वासित गांव के लोगों की मदद की तब मुझे इस मुद्दे की जटिलता का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने उन सभी लोगों को एक एक मंच पर लाने का निर्णय किया।

जनजागर प्रतिष्ठान एक ऐसा मंच है जो भंडारी के द्वारा पुनर्वास संबंधित मुद्दों को उठाने का काम करता है। भंडारी जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, ने कहा कि यह सम्मेलन लभी लोगों के लिए एक खुला मंच है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे जहां वे इन मुद्दों पर बात करेंगे। इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रदर्शन के बजाए एक रचनात्मक बातचीत एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। चार दशक पहले, बोरिव के लोगों को धोम जलाशय के कारण सतारा में

विस्थापित किया गया था, जिसे फिर पुनर्वास किया गया, लेकिन इन्हें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उनमें से कई ग्राम पंचायतों के जरिए कराए जाते हैं। भंडारी ने कहा कि अकेले सातारा जिले में 29 बांध बनाए गए हैं और इन सभी परियोजनाओं में पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं अभी तक लंबित हैं। कोंकण रेलवे परियोजना में 49 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि मुंबई-गोवा राजमार्ग निर्माण के चौथे चरण में लगभग 20 हजार लोगों को विस्थापित किया गया है। इसके अलावा, विदर्भ में जमीन और बिजली परियोजनाओं में 25 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में सिंचाई परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं, राजमार्ग परियोजनाएं, वन परियोजनाएं और आवास परियोजनाओं के मुद्दे पर बात होगी।

सरकार के लिए अच्छा,जनता के लिए बुरा है जीएसटी - कांग्रेस

नई दिल्ली

कांग्रेस ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर को सरकार के लिए अच्छा और लोगों के लिए बुरा बताया है। कांग्रेस का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रत्यक्ष तौर पर उड़ाया गया उपहास है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था। एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नये कर प्रावधान के नुकसानों के बारे में बताया जो कश्मीर के अलावा पूरे देश में 1 जुलाई को लागू किया गया था। कश्मीर में भी यह प्रावधान शुक्रवार को पारित कर दिया गया।

सिबबल ने कहा, कई टैक्स स्लैब- 0. 25, 03, 05, 12, 18 व 28 फीसद हैं। इसका दुखद हिस्सा यह है कि जीएसटी के अलावा राज्य

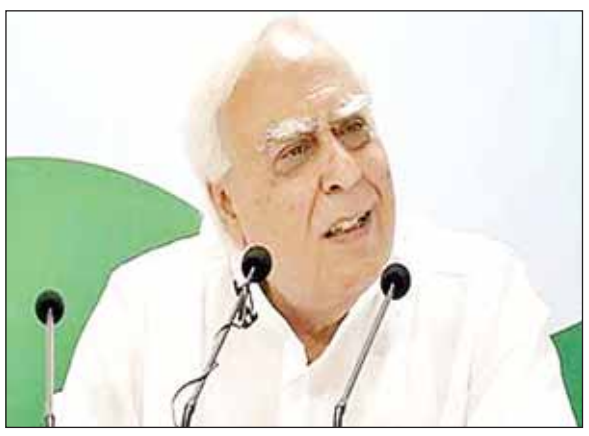

सरकारों को म्यूनिसिपल टैक्स भी लगाना आवश्यक है। उदाहरण देते हुए सिब्बल ने बताया, यदि सिनेमा टिकट 100 रुपये से कम में होता है तब जीएसटी 18 फीसद है और यदि 100 रुपये से अधिक है तो जीएसटी 28 फीसद होगा।

तमिलनाडु में सिनेमा टिकट 100 रुपये से अधिक है जिस पर 28 फीसद का जीएसटी है और 30 फीसद अतिरिक्त टैक्स। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इसका मतलब कि आम आदमी को 100 रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर 58 फीसद मनोरंजन कर और 100 रुपये से कम पर 48 फीसद मनोरंजन कर का भुगतान करना होगा। उन्होंने आगे बताया, हमारे देश में आम आदमी के लिए सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन है। यह किस तरह का टैक्स है? दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने अपने नुकसानों की भरपाई के लिए रोड पर जीएसटी के अलावा अतिरिक्त 2 फीसद का टैक्स लगाया है।

जीएसटी व्यवस्था में दूसरी खामी निकालते हुए उन्होंने कहा कि खुद्र बिक्री वाले आटे और बिस्कुट पर जीएसटी नहीं है जबकि पैकेज्ड पर यह कर लागे है। उन्होंने सवाल किया कि आजकल खुद्रा आटा और बिस्कुट कौन खरीदता है क्योंकि सभी को यह पता है कि पैकेट के सामान अच्छे होते हैं। कांग्रेस नेता ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जीएसटी के इन प्रावधानों के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है जो कर प्रावधान को सरल बनाने के लिए लाया जाना था।

आत्महत्या करने वालों को मुआवजा देना गलत प्रथा - हाईकोर्ट

नई दिल्ली

सार्वजनिक समारोह के दौरान दो युवकों के आत्महत्या करने पर दिल्ली सरकार द्वारा उनके परिवार को मुआवजा देने पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक गलत चलन है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को यह सलाह दी कि वह इन युवकों को दिए शहीद के दर्जे को वापस ले। हाईकोर्ट ने कहा कि यह टैक्स देने वाले लोगों का पैसा है। इस तरह आत्महत्या करने वालों को रपए बांटकर आप गलत मिसाल दे रहे हैं। इससे अन्य लोग भी आत्महत्या करने की तरफ प्रेरित होंगे। आप इस आदेश को वापस क्यों नहीं ले लेते। दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अब तक मृतकों के परिजन को मुआवजे की रकम नहीं दी गई है। वकील अवध कौशिक और पूर्व सैनिक पून चंद आर्या द्वारा लगाई गई इस याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आठ अगस्त को अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

ममता ने दिया बशीरहाट हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश

कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में सांप्रदायिक हिंसा की घटना की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले में कानून अपने ढंग से काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को नवान्न (राज्य सचिवालय) में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बशीरहाट और बादुड़िया में हिंसा की न्यायिक जांच होगी। सुनियोजित तरीके से किसने अफवाह फैलाई और हिंसा फैलाने में किन लोगों ने मदद की उन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होगी। इस

मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ममता ने कहा कि एक भोजपुरी फिल्म में हिंसा के दृश्य को पश्चिम बंगाल की हिंसा बताकर फेसबुक पर डाला गया।

बांग्लादेश की हिंसा के वीडियो फुटेज को पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा बोलकर दिखाया गया। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल में इस तरह के फर्जी वीडियो फुटेज दिखाए गए। इन सबके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक फेसबुक को फेकबुक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भाजपा की गतिविधियां चलती हैं। बशीरहाट में कहां से इतनी संख्या में लोग जमा हुए और कैसे हिंसा को अंजाम दिया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ राज्य की सीमाएं जुड़ी हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को अशांत किया जा रहा है। इसमें विदेशी ताकतों की मदद ली जा रही है।

पश्चिम बंगाल: पुलिस हिरासत में भाजपा के तीन सांसद, बशीरहाट जाने से रोका

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में हिंसा भड़कने के बाद यहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंसाग्रस्त बशीरहाट में कई दलों के नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा की केंद्रीय टीम भी बशीरहाट का दौरा करने पहुंची थी। लेकिन, पुलिस ने भाजपा नेताओं को मध्यग्राम में ही रोक लिया।

बशीरहाट का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम में सांसद मीनाक्षी लेखी, ओम माथुर और सत्यपाल सिंह शामिल थे। पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं की पुलिस के साथ बहस भी हुई। मीनाक्षी लेखी ने कहा

कि अगर राज्य सरकार बशीरहाट में सामान्य स्थिति होने का दावा कर रही है तो फिर हमें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने पुलिस से कहा हम सांसद हैं और सिर्फ तीन ही वहां जाएंगे। आप हमारा साथ दीजिए। लेखी के आग्रह के बावजूद पुलिस ने उन्हें बशीरहाट जाने से रोक दिया।

परमाणु हथियार पर रोक: 122 देशों ने संधि स्वीकारी

अमेरिका और पाक ने किया बहिष्कार

नई दिल्ली

परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी पहली वैश्विक संधि की स्वीकृति के लिए संयुक्त राष्ट्र में 120 से अधिक देशों ने मतदान किया है। हालांकि, भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान सहित अन्य परमाणु क्षमता सम्पन्न देशों ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की खातिर कानूनी तौर पर बाध्यकारी व्यवस्था के लिए हुई वार्ताओं का बहिष्कार किया।

परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि परमाणु अप्रसार के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी पहली बहुपक्षीय व्यवस्था है, जिसके लिए 20 साल से वार्ता चलती रही है। इस संधि पर शुक्रवार को गर्मजोशी और तारीफ के बीच मतदान हुआ, जिसमें इसके पक्ष में 122 देशों ने वोट किया। इस संधि के विरोध में सिर्फ एक देश नीदरलैंडस ने वोट किया जबकि एक देश सिंगापुर मतदान से दूर रहा। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस,

पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इस्राइल जैसे परमाणु क्षमता संपन्न देशों ने इन वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया।

परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के मकसद से कानूनी तौर पर बाध्यकारी व्यवस्था पर वार्ता के लिए इस साल मार्च में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाने के लिए पिछले साल अक्तूबर में 120 से ज्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव पर मतदान किया था। भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान से खुद को दूर रखा था। अक्तूबर में प्रस्ताव पर वोट से दूर रहने को लेकर दिए गए अपने स्पष्टीकरण में भारत ने कहा था कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि प्रस्तावित सम्मेलन परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक समग्र व्यवस्था कायम करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की लंबे समय से रही अपेक्षा पर खरा उतर पाएगा। भारत ने यह भी कहा था कि जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सीडी) निरस्त्रीकरण पर चर्चा के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है। उसने कहा था कि वह परमाणु हथियारों पर समग्र सम्मेलन (सीएनडब्ल्यूसी) पर सीडी में वार्ता की शुरुआत का समर्थन करता है। सीएनडब्ल्यूसी में प्रतिबंध और विलोपन के अलावा सत्यापन भी शामिल है। परमाणु हथियारों के वैश्विक विलोपन के लिए अंतरराष्ट्रीय सत्यापन को जरूरी बताते हुए भारत ने कहा था कि मौजूदा प्रक्रिया में सत्यापन के पहलू को नहीं जोड़ा गया है।

मतदान से दूर रहने के लिए दिए गए अपने स्पष्टीकरण पर कायम रहते हुए भारत ने संधि के लिए हुई वार्ता में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस संधि पर सभी देश दस्तखत कर सकेंगे। कम से कम 50 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद यह संधि प्रभावी हो जाएगी। अमेरिका, रूस और अन्य परमाणु क्षमता संपन्न देशों के साथ-साथ उनके कई सहयोगी देशों ने भी वार्ता से दूरी बनाए रखी। उत्तर कोरिया ने भी वातार् में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस (तीनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और वीटो की ताकत से लैस हैं) के स्थायी प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि उन्होंने, संधि की वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है और इस पर दस्तखत, इसके अनुमोदन या कभी इससे जुड़ा पक्ष बनने का कोई इरादा नहीं रखते है।

16 को मानसून सत्र का सियासी पारा ठंडा रखने के लिए सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली

राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के साथ राजनीतिक पारा गरम है। संसद के मानसून सत्र का तापमान ठंडा रखना सत्तापक्ष के लिए चुनौती है। इसके मद्देनजर ही जहां सरकार ने 16 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इसी दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भाजपा भी अपने राजग सहयोगियों के साथ 16 की शाम बैठक करेगी।

संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसद वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 5 अगस्त को होना है। हालांकि इन दोनों शीर्ष संवैधानिक पदों पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई

कठिनाई नहीं है, मगर देश में नए टैक्स युग जीएसटी के लागू होने क बाद पहले संसद सत्र में सरकार के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। खासकर यह देखते हुए कि छोटे कारोबारियों की जीएसटी से नाराजगी को विपक्षी पार्टियां भी उठाने लगी हैं। इसी तरह राजनीतिक तौर पर कथित गोरक्षकों के हिंसात्मक हमले और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की हालिया घटनाओं को लेकर भी विपक्षी दल केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं।

चीन के साथ सिक्किम सीमा पर जारी तनातनी को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चिंता का इजहार किया है और सरकार से हालात की जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा भी कि बेशक चीन और पाकिस्तान से जुडे. मामले पर पूरा देश एक है और हम सरकार के साथ खड़े हैं।

मगर सरकार को तो इस बात का जवाब देना ही होगा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गांधीनगर में झूले से शुरू हुए अच्छे आगाज के बाद बीच में ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने खड़े हैं। मानसून सत्र में यह मुद्दा विपक्षी पार्टियां संसद में जरूर उठाएंगी।